



इफ्तार : शाम 5.59 (14 मार्च)
सेहरी : भोर 4.42 (15 मार्च)



भारत को आत्मनिर्भर और आधुनिक बनायेगा चिप मैनुफैक्चरिंग : पीएम

पीएम मोदी ने सेमीकंडक्टर के तीन बड़े प्रोजेक्ट का किया ऑनलाइन शिलान्यास

एजेंसी

नयी दिल्ली। भारत ने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में नई शुरुआत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को 'इंडियाज टैकेड' : चिप फॉर विकसित भारत कार्यक्रम में लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपये के तीन सेमीकंडक्टर परियोजनाओं का

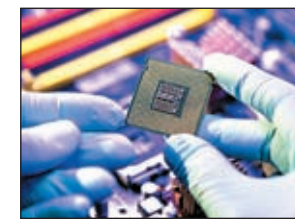
ऑनलाइन शिलान्यास किया। इनमें से 2 प्रोजेक्ट गुजरात और एक असम में है। इस प्रोजेक्ट की नींव रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा-हम उज्ज्वल भविष्य की ओर एक बड़ा कदम उठा रहे हैं। चिप मैनुफैक्चरिंग भारत को आत्मनिर्भरता, आधुनिकता की ओर ले जाएगी। आपको बता दें कि पिछले महीने केंद्रीय कैबिनेट ने तीन सेमीकंडक्टर यूनिट की स्थापना की मंजूरी दी थी। तीनों फैसिलिटीज की मैनुफैक्चरिंग का काम 100 दिनों के अंदर काम शुरू होगा।

प्रधानमंत्री मोदी के विजन से ये काम हो रहा : एन चंद्रशेखरन टाटा ग्रुप के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने कहा कि मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप की मैनुफैक्चरिंग पीएम मोदी के विजन से पूरी हो रही है। यह सभी डिजिटल प्रोडक्ट के लिए फाउंडेशनल इंडस्ट्री है। टाटा ग्रुप के चेयरमैन ने कहा कि हम इस क्रम में 50,000 नौकरियां सृजित करेंगे और यह सिर्फ एक शुरुआत है। आज सेमीकंडक्टर बनाने की हमारी यात्रा शुरू हो गई है।

निवेश की जगह और लागत

गुजरात के धोलेरा में : कुल 91,000 करोड़ रुपये के निवेश के साथ यह देश का पहला कॉमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब होगा।
गुजरात के साणंद में : गुजरात के साणंद में कुल निवेश लगभग 7,500 करोड़ रुपये होगा।
असम के मोरीगांव में : असम के मोरीगांव में सेमीकंडक्टर असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग के लिए प्लांट स्थापित किया जायेगा। कुल निवेश लगभग 27,000 करोड़ रुपये है।

जानें क्या होता है सेमीकंडक्टर चिप



सेमीकंडक्टर चिप सिलिकॉन से बनी होती है और सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल करने के काम आती है। ये चिप एक दिमाग की तरह इन गैजेट्स को ऑपरेट करने में मदद करती है। इसके बिना हर एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम अधूरा है। कंप्यूटर, लैपटॉप, कार, वॉशिंग मशीन, एटीएम, अस्पतालों की मशीन से लेकर हाथ में मौजूद स्मार्टफोन तक सेमीकंडक्टर चिप पर ही काम करते हैं।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक, कहा अवैध खनन रोकें, चिह्नित 369 बालू घाट के संचालन का जिम्मा ग्राम पंचायतों को दें

खबर मन्त्र व्यूटे

रांची। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने बुधवार को प्रोजेक्ट भवन में राज्य में विधि व्यवस्था, रांची में यातायात व्यवस्था, सड़क सुरक्षा एवं अपराध नियंत्रण को लेकर बैठक की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अपराध की घटनाओं पर लगाम लगाएं। उन्होंने कहा कि अपराध मुक्त झारखंड का निर्माण उनकी सरकार की प्राथमिकता है। जमीन खरीद-बिक्री से जुड़े अपराधिक मामलों में सलियन लोगों पर कड़ी कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि अफीम की खेती रोकने के लिए जंगल बचाओ ग्राम समितियों को साथ लेकर लोगों को जागरूक करें। पेज 2 भी देखें...



अपराध मुक्त झारखंड का निर्माण उनकी सरकार की प्राथमिकता
धनबाद में विधि व्यवस्था का संधारण दुरुस्त करें
जमीन खरीद-बिक्री से जुड़े अपराधिक घटनाओं को जांच कर दोषियों पर करें कार्रवाई

अवैध खनन में सलियन लोगों पर कार्रवाई करें : मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में अवैध खनन एक बड़ा मुद्दा है। अवैध खनन को लेकर राज्य की छवि धूमिल हो रही है। अवैध खनन को रोकथाम के लिए गठित टास्क फोर्स को सक्रिय करें। अवैध खनन रोकने के नाम पर सिर्फ वाहनों को पकड़ कर एफआईआर दर्ज करने की खानापूति न करें, बल्कि बिना चालान के वाहनों में कैसे कोयला लोडिंग की जाती है, इसकी भी जांच सुनिश्चित करें।

बालू की उपलब्धता सुनिश्चित करायें अधिकारी, टेंडर प्रक्रिया तेज करें

मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों से राज्य में बालू घाटों की टेंडर प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा। जनता को आसानी से बालू उपलब्ध हो, यह सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैटिगरी-2 वाले चिन्हित 369 बालू घाटों को ग्राम पंचायत स्तर पर संचालित करने की प्रक्रिया शीघ्र पूरी करें। राज्य में 369 बालू घाटों का

संचालन ग्राम पंचायत करेगी तभी ग्रामीण क्षेत्र के अलावा शहरी क्षेत्र में भी बालू की मांग को पूरा किया जा सकेगा। मौके पर सीएम को जानकारी दी गयी कि 369 बालू घाटों का संचालन पंचायत स्तर पर किए जाने का निर्णय लिया जा चुका है। संचालन की सभी प्रक्रिया जल्द पूरी कर ली जाएगी। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि राज्य में कैटिगरी-2 की 444 बालू घाटों का टेंडर फाइनल कर दिया गया है। वहीं 444 बालू घाटों में 241 घाटों का एमडीओ एजेंसी फाइनल कर लिया गया है। 116 एमडीओ एजेंसियों के साथ एग्जिट कर लिया गया है, पर्यावरण स्वीकृति मिलते ही इन सभी 116 घाटों में बालू का उठाव कार्य प्रारंभ किया जा सकेगा।

इडी को 10 कंपनियों के बारे में पता चला, मनी लाउंड्रिंग के साक्ष्य मिले

विधायक अंबा प्रसाद के दूसरे आवास पर भी पहुंची इडी

खबर मन्त्र व्यूटे

रांची/हजारीबाग। बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद के आवास पर 40 घंटे छापेमारी हुई। विधायक और सीओ शशिभूषण सिंह के रांची, हजारीबाग, मुंबई, धनबाद में छापेमारी की गयी। छापेमारी के दौरान कंपनी के दस्तावेज और महत्वपूर्ण दस्तावेज को इडी जब्त कर चुकी है। बुधवार सुबह करीब 11 बजे इडी की टीम ने दूसरे घर पर भी छापेमारी शुरू की। पहले आवास के स्टॉफ को बुलाया गया। इसके बाद विधायक अंबा प्रसाद की मां निर्मला देवी को भी लाया गया। निर्मला देवी करीब आधे घंटे तक वहां मौजूद रहीं। इसके बाद उन्हें उनके पुराने घर भेज दिया गया।
इडी के हाथ लगे कई सबूत : जिस घर में छापेमारी हुई, उस घर को इडी ने सुरक्षा घेरे में लिया। इडी ने छापेमारी के दौरान इलेक्ट्रिक गजट जब्त किया है। छापेमारी के

अंबा और योगेंद्र साव के खिलाफ ईसीआईआर दर्ज हजारीबाग में बेशकीमती जमीन पर कब्जा करने के मामले में उभरे विवाद के बाद इडी ने अंबा प्रसाद और योगेंद्र साव के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी की तलाश की और दोनों के खिलाफ ईसीआईआर दर्ज किया। इसके बाद मंगलवार सुबह करीब सात बजे रांची, हजारीबाग और मुंबई स्थित ठिकानों पर छापे मारा गया।
दौरान अंबा प्रसाद की मां पूर्व विधायक निर्मला देवी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं थीं। इडी ने योगेंद्र साव के बेटे अंकित राज, बेटे अनुप्रिया और अन्य रिश्तेदारों के नाम पर बनी 10 कंपनियों को भी इस छापेमारी के दायरे में शामिल किया है। इन कंपनियों के माध्यम से मनी लाउंड्रिंग को अंजाम देने से संबंधित दस्तावेज भी इडी को मिले हैं।

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
झारखण्ड सरकार

उत्तर पूर्व राज्यों की संस्कृति एवं इतिहास पर राष्ट्रीय संगोष्ठी

19 से 22 मार्च, 2024

असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, सिक्किम, नागालैंड के विषय विशेषज्ञों की प्रस्तुति

आप सभी सादर आमंत्रित हैं !

स्थान : संस्थान सभागार
पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 6:00 बजे तक

आयोजक :-
डॉ. रामदयाल मुण्डा
जनजातीय कल्याण शोध संस्थान,
मोरहाबादी, राँची

PRNO 322560 (Schedule Tribe, Schedule Caste, Minority and Backward Class Welfare Department) IPRD 23-24



फर्जी लाइसेंस मामले में मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा



प्रयागराज। बांदा जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे अंतरराज्यीय गिराह (आईएस-191) के सरगना मुख्तार अंसारी को गाजीपुर के फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही मुख्तार अंसारी पर 2 लाख 2 हजार रुपये का जुर्माना भी कोर्ट ने लगाया है।

अमेरिका में एक ओर भारतीय छात्र की मौत

वॉशिंगटन। अमेरिका में भारतीय छात्रों की मौत का सिलसिला जारी है। रिपोर्ट के अनुसार, एक 27 वर्षीय छात्र, जिसकी पहचान वैक्टरमण पितला के रूप में हुई है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में अपनी मास्टर डिग्री की पढ़ाई कर रहा था, 9 मार्च को पलोरिडा राज्य में एक रेट की दुर्घटना में छात्र की मृत्यु हो गई। वैक्टरमण, जो काजीपेट से हैं, आईयूपीयूआई में मास्टर्स के छात्र थे और मई में अपनी डिग्री प्राप्त करने वाले थे। जानकारी के अनुसार, दुर्घटना दोपहर करीब 12.30 बजे विस्टरिया द्वीप के पास प्युरी प्लेग्राउंड में हुई। इसके साथ ही एक अन्य जिसकी लड़का जो दूसरा निजी वॉटरक्राफ्ट चला रहा था, वह घायल नहीं हुआ।

अब अहमदनगर का नाम होगा अहिल्या नगर

मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कई फैसले किए हैं। शिंदे कैबिनेट ने अहमदनगर जिले का नाम बदलकर अहिल्या नगर कर दिया है।

भारतीय स्टेट बैंक ने उच्चतम न्यायालय को बताया राजनीतिक दलों ने अप्रैल 2019 से 15 फरवरी तक 22,217 चुनावी बांड खरीदे

एजेंसी

नयी दिल्ली। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने बुधवार को उच्चतम न्यायालय को बताया कि इस साल एक अप्रैल 2019 से 15 फरवरी के बीच राजनीतिक दलों ने कुल 22,217 चुनावी बांड खरीदे और 22,030 बांड पुनर्प्राप्त किए।

शीर्ष अदालत में दावर एक अनुपालन हलफनामे में एसबीआई ने कहा कि अदालत के निर्देश के अनुसार, उसने 12 मार्च को व्यावसायिक समय बंद होने से पहले भारत के चुनाव आयोग को चुनावी बांड का विवरण उपलब्ध करा दिया है।



राजनीतिक दलों के नाम और बांड के मूल्यवर्ग जैसे विवरण भी दिये

इसमें कहा गया है कि प्रत्येक चुनावी बांड की खरीद की तारीख, खरीदार के नाम और खरीदे गए बांड के मूल्यवर्ग सहित विवरण प्रस्तुत किए गए हैं। एसबीआई के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा द्वारा

दावर हलफनामे में कहा गया है कि बैंक ने चुनाव आयोग को चुनावी बांड के नकदीकरण की तारीख, योगदान प्राप्त करने वाले राजनीतिक दलों के नाम और बांड के मूल्यवर्ग जैसे विवरण भी दिए हैं। 11 मार्च को, मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता

चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति विवाद पर सुप्रीम कोर्ट कल करेगा सुनवाई

उच्चतम न्यायालय मुख्य न्यायाधीश के बजाय एक केंद्रीय मंत्री समेत अन्य वाले पैनल की सिफारिश पर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने के दिसंबर 2023 के (संशोधित) कानूनी प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति एम एम सुदेश और बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने बुधवार को याचिकाकर्ताओं के अधिकांशों को बताया कि सूचीबद्ध करने संबंधी जानकारी सीजेआई की ओर प्राप्त हुई है और मामले को 15 मार्च के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। वकील प्रशांत भूषण ने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष एडीआर की ओर से याचिका का उल्लेख किया था।

वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने समय बढ़ाने की मांग करने वाली एसबीआई की याचिका को खारिज कर दिया था और उसे 12 मार्च को व्यावसायिक घंटों के अंत तक चुनाव आयोग को चुनावी बांड के विवरण का खुलासा करने का आदेश दिया था।

यूसीसी को मिली राष्ट्रपति की मंजूरी

नयी दिल्ली। उत्तराखंड के समान नागरिक संहिता (सीए) बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही अब समान नागरिक संहिता पर कानून बन गया है। उत्तराखंड सरकार ने सामान नागरिक संहिता लागू करने के लिए नियमों/उपनियमों को बनाने के लिए पांच सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया है। नियमावली बनने के बाद उत्तराखंड सरकार द्वारा इसे पूरे राज्य में लागू कर दिया जायेगा। नियम बनाने वाली सदस्यों वाली कमेटी में पूर्व आईएसएस शत्रुघ्न सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौर, दून विवि की कुलपति सुरेखा डंगवाल, एडीजी अमित सिन्हा और उत्तराखंड के स्थानीय आयुक्त अजय मिश्रा शामिल हैं। यह कमेटी जल्द ही एक मीटिंग कर यूसीसी कानून लागू करने के लिए आवश्यक नियम उप नियम बनाने का काम शुरू करेगी।

एनसीसी में तीन लाख कैडेटों को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी

एजेंसी

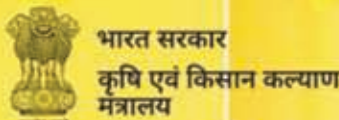
नयी दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) के विस्तार के लिए तीन लाख कैडेट रिक्रियों को भरने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे देश भर के शैक्षणिक संस्थानों में एनसीसी की बढ़ती मांग को पूरा करने की उम्मीद है। इस प्रस्ताव को मंजूरी के बाद एनसीसी में अब कैडेटों की स्वीकृत संख्या 20 लाख हो जायेगी, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा वदीर्धारी युवा संगठन बना देगी। वर्ष 1948 में केवल 20,000 कैडेटों के साथ एनसीसी का गठन हुआ था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एनसीसी को एक वैकल्पिक विषय के रूप में पेश किए जाने के साथ, एनसीसी का यह विस्तार देश के



भावो मार्गदर्शक के रूप में अहम भूमिका निभाने की युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में बड़ा कदम होगा। इस विस्तार से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रिक्रियों का अनुपातिक वितरण होगा और एनसीसी के इच्छुक शैक्षणिक संस्थानों की प्रतीक्षा सूची में कमी आएगी। इस विस्तार योजना में चार नए समूह मुख्यालयों और दो नई एनसीसी इकाइयों की स्थापना शामिल है। इस विस्तार योजना का एक महत्वपूर्ण पहलू

यह है कि इसमें पूर्व सैनिकों को एनसीसी प्रशिक्षकों के रूप में रोजगार देने का प्रस्ताव शामिल है, जिससे उनके कौशल और लंबे अनुभव का लाभ उठाया जा सके। इस पहल से एनसीसी कैडेटों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण सुनिश्चित हो सकेगा और उनके लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

यह विस्तार अनुशासन, नेतृत्व और सेवा की भावना से ओतप्रोत मार्गदर्शक तैयार करने के प्रति समर्पण का प्रतीक है। एनसीसी का लक्ष्य एक ऐसा वातावरण तैयार करना है, जहां युवा राष्ट्र निर्माण में सक्रिय योगदान दें। यह पहल 'अमृतपीढ़ी' के प्रेरित, अनुशासित और देशभक्त युवाओं के आधार का विस्तार करेगी जो 'विकसित भारत' के लक्ष्य को हासिल करने में योगदान देंगे।



भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण
मंत्रालय



पूर्वी भारत में शहद क्रांति का आगाज

झारखंड में स्थापित होगी अंतरराष्ट्रीय स्तर की अत्याधुनिक शहद टेस्टिंग लैब
हनी हब बनने से शहद उत्पादक हजारों किसानों को मिलेंगे निर्यात के अवसर

झारखंड और आसपास के राज्यों- बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, ओडिशा की अनूठी शहद किस्मों को मिलेगी अंतरराष्ट्रीय पहचान
एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केन्द्र एवं मधुमक्खी पालन और बांस संवर्धन परियोजना की भी सौगातें

शिलान्यास कार्यक्रम

मुख्य अतिथि

श्री अर्जुन मुंडा

माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण व जनजातीय कार्य मंत्री, भारत सरकार

गरिमामयी उपस्थिति- श्री संजय सेठ, सांसद रांची लोकसभा
श्री राजेश कच्छप, विधायक, खिजरी विधानसभा

14 मार्च, 2024
दोपहर 2 बजे

स्थान- भाकृअनुप - राष्ट्रीय कृषि उच्चतर प्रसंस्करण संस्थान
नामकुम, रांची, झारखंड

राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन

कृषि विज्ञान केन्द्र- खूंटी, रांची, गुमला, सिमडेगा, सराईकेला, पश्चिमी सिंहभूम



